THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRl MAUJKARJUN: (a) and (b) 'Prison' is a State subject and no information is available on this matter with the Ministry of Railways.

No, Sir-

Doe$_s$ not arise.

'Prison? is a State subject.

पश्चिम रेलवे में रोजगार के अवसर

4549. **श्री गोपालसिंह जी० सोलंकी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम रेलवे जोन में रोजगार के अवसर कम हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान रोजगार के कितने अवसरों के सृजन का प्रस्ताव किया गया था ;

(ग) पश्चिम रेलवे में गत तीन वर्षों से नैमित्तिक कर्मचारियों सहित कुल कितने कर्मचारी कार्यरत हैं ; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान कितने कर्मकारों को नियोजित किया गया और उनमें से नैमित्तिक कर्मकारों की संख्या कितनी है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

Project ot Calcutta port Irust

4550 SHRI GHUFRAN AZAM: Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to refer to the answer to Unstarred Question No, 1091 given in the Rajya Sabha on the 6th May, 1992 and stata:

(a) the details of statutory clearance that has been included in the project of Calcutta Port Trust and which are to be taken clearance of;

(b) whether 'these also include specific clearance to be sought from the Department of Environment;

(c)whether air pollution, traffic congestion and other hardships are likely to be increased by the implementation of the project; and

(d) if so, the details thereof and the steps to be taken by Government to withhold the project till full investigations are made?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT (SHRI JAGDISH TYTLER):

(a) Clearance from Calcutta Improvement Trust and Calcutta Municipal Corporation will be required- Calcutta Municipal Corporation in turn will obtain clearance from Director Fire Serv'ces, Govt, of West Bengal and Calcutta Metropolitan Development Authority.

(to) No, Sir. However, Environment Impact Assessment/Environment Management Plan will be prepared and submitted to the Ministry of Environment for clearance.

(c) and (d) A report showing the traffic dispersal, water supply, sewage system/drainage system in the project areas have already been sent to Calcutta Municipal Corporation for obtaining; clearance,

D.T.C. services

4551. SHRI V. NARAYANASAMY: Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether Government propose to extend D.T.C. services on Gurgaon/ Ajmeri Gate/Shivaji Stadiurfl/Solina to I.S.B.T, and other terminals like Nehru Place, Safdarjung terminal/Lajpat Nagar etc.; and

(b) whether Government also propose to extend the frequency on this route

and the last trip up to 2100 hours in order to cater to the needs of the employees connected with Parliament Sessions; if so, by when and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE OF THE MliNlSTRY OF SURFACE TRANSPORT (SHRT JAGDISH TYTLER):
(a) No, S8r.

(b) On account of shortage of buses, there is no proposal to extend the frequency on this route.

On ccount ot increased terrorist activites in Northern India, Delhi Administration had issued instruction in 1987 for dscomtinuation of bus services from Delhi towards adjoining towns of Haryana and Punjab after 2000 hrs.

Accordingly, the services on Gurgaon route were adjusted in such a way that the last bus ie:ives Shivaji Stadium at ".30 p-m.

दिल्ली परिवहन निगम के पद-अधिकारियों के खिलाफ आरोप

4552. **डा. जिनेन्द्र कुमार जैन :**
श्री वीरेन जे० शाह :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में दिल्ली परिवहन निगम के बहुत से शीर्षस्थ पदाधिकारियों का स्थानान्तरण किया गया है और वह आशंका व्यक्त की गई है कि वे कतिपय मामलों में हुई अनियमितताओं में शामिल थे, जिसके फलस्वरूप निगम को करोड़ों रुपए की हानि हुई;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में संदेह के घेरे में कौन-कौन से अधिकारी हैं और क्या इनसे संबंधित मामलों की जांच का कार्य केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंप दिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उन सभी अधिकारियों को उनके विरुद्ध जांच कार्य पूरा हो जाने तक सेवा से निलम्बित न कि जाने के क्या कारण हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) :(क) से (ग) बेकार टायरों की बिक्री पर बिक्री कर में कटौती/वसूली में तथाकथित अनियमितताओं की केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच कि जाने तक दि.प.नि. के 6 अधिकारियों तथा 4 कर्मचारियों को अभी हाल ही में स्थानान्तरित किया गया है। इसमें कुल लगभग 2 लाख रुपये की राशि अंतर्ग्रस्त है।

चूंकि दिल्ली परिवहन निगम के निदेशक मण्डल को किसी बदनीयती का पता नहीं चला है और अपनाई गई प्रक्रिया, पूर्व-पद्धति के अनुरूप थी, इसलिए दिल्ली परिवहन निगम का निदेशक मण्डल ने केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा मामले की जांच पूरी किए जाने तक इन अधिकारियों को मुअत्तल करना उचित नहीं समझा।

Construction of platforms in Bombay High

4553. SHRI SHANTI TYAGI: Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether the Hindustan Shipyard Limited has pleaded with his Ministry to intervene with regard to the contract of construction of tour platforms in the Bombay High and the laying of pipelines; and

(b) whether this request by the Hindustan Shipyard was necessitated due *to* the large number of tenders being sent by the foreign companies as compared to the Indian companies; and

(c) if so, what is Government's reaction thereto?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT (SHRl JAGDISH TYTLER):